



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष 1941 (श10)

(सं० पटना 1350) पटना, मंगलवार, 24 दिसम्बर 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर 2019

सं० 06/विधायी-03-01/2019,परि०-9487—मोटर वाहन अधिनियम-1988 (अधिनियम संख्या 59/88) की धारा-211 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-163 में संशोधन करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी के लिए संशोधन का प्रारूप अधिसूचना संख्या-9248, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा इस संशोधन के विरुद्ध उसके प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के अन्दर आपत्तियाँ एवं सुझाव समर्पित करने हेतु सूचना दी गयी थी।

2. उपर्युक्त निर्धारित अवधि के अन्दर कोई भी आपत्ति या सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

3. अतः बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-163 में संशोधन करने के लिए निम्नांकित नियम बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:**—(i) यह नियमावली बिहार मोटरवाहन(संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(ii) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(iii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2. **बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-163 ख के उपनियम(2),(3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—**

**163 ख (2)—प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की वैधता:**—“किसी भी मोटरवाहन के प्रथम निबंधन से एक वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाली अधिकृत एजेंसी द्वारा अधिकतम छह माह की अवधि के लिए ही ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र’ निर्गत किया जायेगा,

परंतु BS IV या BS VI मानक की गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 माह की अवधि के लिए वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र’ निर्गत किया जा सकेगा।”

**163 ख (3)—प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र का स्वरूप एवं विधान:**—“अधिकृत एजेंसी द्वारा मात्र ऑनलाईन ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र’ निर्गत किया जा सकेगा जो 14 साइज में निर्गत किया जायेगा।”

3. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-163 घ को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

**163 घ-प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना:-**“कोई भी ‘व्यक्ति’, ‘अधिकृत मोटर वाहन कंपनियों के सर्विस सेन्टर,” ‘मोटर वाहन ईंधन आपूर्ति केन्द्र (पेट्रोल पंप, डीजल पंप इत्यादि सभी Fuel Stations)” एवं कंपनी अधिनियम, 2013, के अंतर्गत निबंधित कोई ‘कंपनी’ केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-115 के उप नियम (2), (3), (4), एवं (5) के अधीन मोटर वाहनों के गैस और धुएं के उत्सर्जन स्तर की जांच हेतु तथा ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र’के निर्गमन हेतु प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (राज्य परिवहन आयुक्त) से ऑनलाईन अनुरोध कर सकता है।”

4. बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम-163 ड. के उपनियम (1), 2(i), (ii), 3(i),(iii) एवं 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

**163 ड.-अनुज्ञप्ति का निर्गमन एवं नवीकरण:-**(1) अनुज्ञप्ति की स्वीकृति एवं नवीकरण हेतु आवेदन यथा स्थिति प्रपत्र एल0टी0एस0ए0 अथवा एल0टी0एस0आर0 में ‘ऑनलाईन’ अनुज्ञापन प्राधिकार को समर्पित किया जायेगा।

**2 (i)** अनुज्ञप्ति के आवेदन के साथ नियमावली के नियम-163 छ उप नियम (4) के अनुसार फीस ‘ऑनलाईन’ जमा की जायेगी।

**2 (ii)** अनुज्ञप्ति नवीकरण के आवेदन के साथ नियम-163 छ उपनियम (4) के अनुसार फीस ‘ऑनलाईन’ जमा की जायेगी।

**3(i)** आवेदक मोटरवाहनों के रख-रखाव एवं उसकी सर्विसिंग आदि का व्यवसाय करता हो। आवेदक स्वयं या उसका स्टाफ मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल अथवा ऑटोमोबाइल अभियंत्रण में डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी हो अन्यथा इन्टरमीडियट/12वीं कक्षा (विज्ञान के साथ) उत्तीर्ण हो, या मोटरवाहन से संबंधित किसी ट्रेड में आई0टी0आई0 उत्तीर्ण हो।

**3(iii)** जहां वाहनों की जांच किया जाना प्रस्तावित हो, वह परिसर आवेदक के स्वामित्व में अथवा उसके द्वारा लीज पर लिया गया अथवा उसके नाम से किराये पर लिया गया और उस परिसर में जांच कार्य के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध हों।

आवेदक “चलन्त प्रदूषण जांच केन्द्र” भी संचालित कर सकता है, परंतु प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए अन्य मानक पूरा करने के अतिरिक्त जिस वाहन पर ‘चलन्त प्रदूषण जांच केन्द्र’ स्थापित हो उक्त वाहन को राज्य के अंतर्गत व्यवसायिक वाहन के रूप में निबंधित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह मोटरवाहन अधिनियम, 1988 केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 तथा बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के अध्याधीन अपेक्षित शर्तें पूर्ण करता हो तथा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अनुसार अपेक्षित करों का भुगतान कर रहा हो। ‘चलन्त प्रदूषण जांच केन्द्र’ की अनुज्ञप्ति किसी जिला क्षेत्र के लिए स्वीकृत की जा सकेगी।

**4.** “अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम-163 ड. (i) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर तथा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक ने इस नियम के उप-नियम (2) एवं (3) की अध्यापेक्षाओं को पूरा कर दिया है, अनुज्ञप्ति दे अथवा नवीकृत कर सकेगा।

यदि आवेदक उपरोक्त शर्त पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदक की अन्य अहर्ता से संतुष्ट होकर अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु “ओपबन्धिक सहमति”(Provisional Consent) प्रदान की जा सकती है। इसकी सूचना आवेदक को प्राप्त होने की तिथि से एक माह (30 दिन) अथवा अधिकतम तीन माह (90 दिन) के अंतर्गत अपेक्षित उपकरण स्मोकमीटर या गैस एनलाईजर (या अन्य कोई अपेक्षित उपकरण जो आवश्यक हो) अपने व्यापार परिसर में लगाया जा सकेगा। तदोपरांत इसका सत्यापन कराकर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है।”

5. बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम-163 छ के उपनियम (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

**163 छ (4)-**“इस नियम के अधीन परिवहन आयुक्त को भुगतये फीस की दर निम्नलिखित होगी :-

क	मोटरवाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिये फीस	5000.00
ख	मोटरवाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र की अनुज्ञप्ति की नवीकरण करने के लिये फीस	5000.00
ग	मोटरवाहनों की जांच हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र की द्वितीयक अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिये फीस	500.00
घ	नियम 163 छ के उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिये फीस।	200.00
च	मोटरवाहन की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के अनुज्ञप्ति निर्गमन/नवीकरण करने हेतु आवेदन फीस	1000.00
छ	मोटरवाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के स्थल परिवर्तन हेतु आवेदन फीस	1000.00
ज	मोटरवाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के स्थल परिवर्तन हेतु निरीक्षण फीस	1000.00

“इस मद की सभी राशि, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन समुचित जमा शीर्ष में ऑन लाईन जमा की जा सकती है।”

बिहार-राज्यपाल के आदेशसे,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सरकार के सचिव।

**The 24<sup>th</sup> December 2019**

No. 06/Vidhayi-03-01/2019,Pari-9487--In exercise of powers vested under Section-211 of Motor Vehicle Act, 1988 (Act No-59,1988), to make amendment in Rule-163 of the Bihar Motor Vehicle Rules,1992 (as amended from time to time) the draft amendment, was published vide Notification No.-9248, dated-16<sup>th</sup> December, 2019 for inviting objections and suggestions within seven days of its publication under section-212 of the said Act.

2.No objections and Suggestions have been received within the above prescribed period from the public.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section-211 of the said Act, the Governor of Bihar is pleased to make following rules to amend the Rule-163 of the Bihar Motor Vehicles, 1992 :-

**1.Short Name, extension & effect:**

- (i) These Rules shall be called as Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rules, 2019.
- (ii) It will be effective with immediate effect.
- (iii) It will extend to the whole State of Bihar.

**2. Rule -163 b, sub rule (2) & (3) of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 will be substituted as follows;**

**163 b(2):** Validity of Pollution under Control (PUC)Certificate: Any Authorized Agency issuing PUC Certificate for Motor Vehicles, being more than one year old from its first Registration, can issue PUC Certificates valid for maximum of six months, Provided PUC Certificate for BS-IV or BS-VI Vehicles can be issued with validity of twelve (12) months.

**163 b (3): Size & Procedures of PUC Certificates;** PUC Certificates can be issued online only, by Authorized Agency /Agencies, which must be in A 4 size.

**3. Rule - 163 d of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 will be substituted as follows;**

**163 d : Establishment of PUC Centers ;** “ Any person “ , “ Service Centers of Authorized Motor Vehicle Companies”, “ Motor Vehicle Fuelling Centers ( Petrol Pump , Diesel Pump , etc ) & “ Any Registered Company registered under ‘Companies Act , 2013 “ can request online , for establishment of PUC Centre under Rule - 115 (sub rule 2,3,4 & 5 ) with a purpose of testing emission of gases &smokes of Motor Vehicles followed by issuing PUC Certificates.

**4. Rule 163 e, sub rule 1, 2(i), 2(ii), 3 (i), 3(iii) & 4 will be substituted as follows;**

**163 e: Issuance of License & its Renewal:** (1) Application for Sanction &Renewal will be submitted online to the Licensing Authority, respectively in Form LTSA or LTSR.

**2(i)** With Application for License, requisite fee will be deposited online, prescribed under Rule 163 g , sub rule (4).

**2(ii)** With Application for renewal of License, requisite fee will be deposited online, prescribed under Rule 163 g, sub rule (4) .

**3(i)** Applicant must be doing business for maintenance & servicing of Motor Vehicles. Applicant himself or their staff should be a Degree holder/Diploma holder in Mechanical/Electrical or Automobile Engineering /12thPass (with science) or having I T I pass in any trade related with Motor vehicle.

**3(iii)** The place, at which vehicles are proposed to be tested, must be in ownership of Applicant or under lease/rent, & having sufficient infrastructure for testing within the premises.

The applicant can operate “MOBILE PUC Centre “, but in addition to compliance of other parameters for that vehicle upon which “MOBILE PUC Centre “, has been set up, it should be registered as a commercial vehicle within State of Bihar . That Motor Vehicle must be complying provisions of MV Act, 1988 (as amended in 2019) CMV Rules,1989,

Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 & must be paying Motor Vehicle Taxes as prescribed under Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994. License for “MOBILE PUC Centre “ can be granted for specific district.

4. Licensing Authority after receiving applications under Rule 163 e(i) and being satisfied that provisions of sub rule (2)& (3) of this rule are complied, can grant License or its renewal.

If applicants are not capable to fulfill above mentioned criteria, but Licensing Authority is satisfied with other eligibilities, Provisional Approval can be granted. Within one month (30 days) to three months (90 days) from receiving such Provisional Approval by applicant, required equipment smoke meter or gas analyzer can be set up within premises for testing. Afterwards, getting it verified, Licensing Authority can grant & issue Licenses.

**5. Rule 163 f, sub rule (4) will be substituted as follows;**

**163 f (4) :** Fee payable to State Transport Commissioner under this rule will be as follows :

(a) Fee for issuing License to PUC Centre for testing vehicles:	5000
(b) Fee for Renewal of License of PUC Centre for testing vehicles:	5000
(c) Fee for issuing Duplicate License of PUC Centre for testing vehicles:	500
(d) Fee for Appeal against order of Licensing Authority under Rule 163 f:	200
(e) Application Fee for Issuance /Renewal of PUC Centre License for testing vehicles:	1000
(f) Application Fee for change of site of PUC Centre for testing vehicles:	1000
(g) Inspection Fee for Site Change of PUC Centre for testing Vehicles:	1000

Total amount under this head can be credited online to prescribed 'Receipt Head' under the control of State Transport Commissioner.

By the order of Governor of Bihar,  
Sanjay Kumar Agrawal,  
*Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1350-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>